आकाशवांणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
गुरुवार 26.03.2026
समय 1305

मुख्य समाचार :–

- केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने होटल और रेस्तरां को उपभोक्ताओं से एलपीजी शुल्क और ईंधन लागत वसूली जैसे अतिरिक्त शुल्क न लेने का निर्देश दिया।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रिमंडल के सदस्यों को जिलों का नियमित भ्रमण कर विकास योजनाओं की जमीनी समीक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
- राज्य आपदा मोचन निधि व राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि मद के तहत प्राप्त प्रस्तावों के अनुमोदन के लिए राज्य कार्यकारिणी समिति की सचिवालय में हुई बैठक। विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी मिली।
- नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम की कार्यकारिणी बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

केंद्र निर्दे□ा

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने होटल और रेस्तरां को निर्देश दिया है कि वे उपभोक्ताओं से एलपीजी शुल्क और ईंधन लागत वसूली जैसे अतिरिक्त शुल्क न लें। प्राधिकरण ने कहा है कि वह देशभर में इस पर निगरानी रख रहा है और इसका उल्लंघन करने पर उचित कार्रवाई की जाएगी तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। प्राधिकरण ने बताया कि सेवा शुल्क संबंधी मौजूदा दिशानिर्देशों से बचने के लिए ऐसे शुल्क लगाए जा रहे हैं। प्राधिकरण ने कहा कि ऐसे मामलों में लोगों को होटल या रेस्तरां से बिल से शुल्क हटाने का अनुरोध करना चाहिए।

मुख्यमंत्री बैठक

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रिमंडल के सदस्यों को जिलों का नियमित भ्रमण कर विकास योजनाओं की जमीनी समीक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सचिवालय में मंत्रियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य में संचालित विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि मंत्रीगण अपने–अपने विभागों की योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर वास्तविक प्रगति का आकलन करें। साथ ही स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों से संवाद स्थापित कर योजनाओं की जमीनी स्थिति की जानकारी प्राप्त करें। मुख्यमंत्री ने जनसमस्याओं के त्वरित समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं का समयबद्ध और प्रभावी कार्यान्वयन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और जिला स्तर पर विकास कार्यों की नियमित निगरानी से योजनाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा तथा शासन के प्रति जनता का विश्वास भी सुदृढ़ होगा। मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों से जुड़े विभागों सड़क, पेयजल, ऊर्जा, सिंचाई और भवन निर्माण के बीच बेहतर समन्वय पर विशेष बल देते हुए कहा कि समन्वित प्रयासों से विकास परियोजनाओं को निर्धारित समय–सीमा में पूरा किया जा सकता है।

मेरी योजना पुस्तक

प्रदेश के कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग की ओर से देहरादून में 'मेरी योजना' पुस्तकों के संबंध में विचार गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी में जनकल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचाने की रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने राज्य सरकार की योजनाओं को आमजन तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचाने और उनके बेहतर क्रियान्वयन के लिए सुझाव प्रस्तुत किए। कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के सचिव दीपक कुमार ने बताया कि पुस्तकों में राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और सेवाओं का सरल ओर सहज भाषा में विवरण प्रस्तुत किया गया है।

इन पुस्तकों की प्रतियां राज्य के सभी जिलों और विकासखण्डों में वितरित की गई हैं। साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों, विभागाध्यक्षों, राजकीय पुस्तकालयों और जिला स्तरीय कार्यालयों तक इन्हें उपलब्ध कराया गया है, जिससे योजनाओं की जानकारी ग्राम पंचायत स्तर तक पहुंच सके।

चैत्र नवरात्रि

प्रदेश में आज राम नवमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हालांकि, कुछ हिस्सों में आज पूर्वाह्न तक महाअष्टमी और उसके बाद रामनवमी मनाई जा रही है। प्रदेश के विभिन्न मंदिरों में सुबह से ही पूजा–अर्चना और विशेष अनुष्ठानों का आयोजन किया जा रहा है। चैत्र नवरात्रि के महाअष्टमी पर्व के पावन अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज अपने शासकीय आवास पर परिवार सहित विधि–विधान से कन्या पूजन किया। इस दौरान उन्होंने नौदुर्गा स्वरूपा कन्याओं का सम्मानपूर्वक पूजन कर उनका आशीर्वाद लिया। कैबिनेट मंत्री ने कन्याओं के चरण पखारकर उन्हें चुनरी ओढ़ाई और विधिपूर्वक आरती उतारी श्रद्धा भाव से कन्याओं को भोजन कराया।

वित्तीय स्वीकृतियां

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में राज्य आपदा मोचन निधि व राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि मद के तहत प्राप्त प्रस्तावों के अनुमोदन के लिए राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई। इस दौरान जिलों से प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों को संस्तुति दी गई। बैठक में विभिन्न जिलों में भूस्खलन नियंत्रण, बाढ़ सुरक्षा और ड्रेनेज से जुड़े अनेक कार्यों को मंजूरी दी गई। इनमें नैनीताल, पिथौरागढ़, हरिद्वार, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी और देहरादून जिलों के तहत कई परियोजनाएं शामिल हैं। जिनमें सुरक्षा दीवार निर्माण, जल निकासी सुधार और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षात्मक कार्य प्रमुख हैं। इसके आलवा राज्य आपदा मोचन निधि के तहत विभिन्न मदों में अतिरिक्त धनराशि आवंटन से संबंधित प्रस्तावों के सापेक्ष 34 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृतियों को कार्योत्तर अनुमोदन भी प्रदान किया गया। मुख्य सचिव ने समिति के समक्ष प्रस्तावों को जिला स्तरीय समिति की सिफारिश पर जिलाधिकारी के माध्यम से प्रेषित करने को कहा। उन्होंने सिंचाई विभाग को नदियों की ड्रैजिंग–माइनिंग के लिए शीघ्र एसओपी जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही, बाढ़ सुरक्षा से जुड़े प्रस्तावों को विभागीय समिति द्वारा तकनीकी परीक्षण के बाद राज्य कार्यकारिणी समिति के समक्ष लाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि जिन नदियों में प्रतिवर्ष कटान की समस्या के कारण कार्य कराना पड़ता है, उन्हें चिन्हित कर उनके चैनलाइजेशन की योजना तैयार की जाए। उन्होंने सितारगंज में बैगुल नदी के लिए अध्ययन कराने के निर्देश भी दिए।

नगर निगम

नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम की कार्यकारिणी बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष 2026–27 को लेकर अहम फैसले लिए गए। नगर निगम सभागार में महापौर गजराज सिंह बिष्ट और नगर आयुक्त परितोष वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बजट प्रस्तावों पर विचार करते हुए राजस्व बढ़ाने के साथ ही करदाताओं को राहत देने वाले कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में नगर निगम की आय बढ़ाने के उद्देश्य से निगम के स्वामित्व वाली दुकानों के किराए में वृद्धि का निर्णय लिया गया। साथ ही विभिन्न नामांतरण प्रस्तावों को भी स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं नव सम्मिलित क्षेत्रों के व्यवसायिक भवनों के लिए राहत भरा फैसला लेते हुए यह तय किया गया कि आगाामी 31 मार्च, 2026 से पहले संपत्ति कर जमा करने पर 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसके अलावा नगर निगम ने करदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए भी निर्णय लिया गया। जिन भवन स्वामियों का 1 अप्रैल, 2026 तक कोई बकाया नहीं होगा, उन्हें वित्तीय वर्ष 2026–27 में भी 31 जुलाई, 2026 तक भवन व स्वच्छता कर जमा करने पर 25 प्रतिशत की छूट का लाभ मिलेगा।

जिलाधिकारी समीक्षा

हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सभी स्कूलों और कॉलेजों में छात्र–छात्राओं की उपस्थिति 90 प्रतिशत से कम न होने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए अभिभावकों के साथ नियमित बैठकें आयोजित करने को कहा गया है। मध्याह्न भोजन योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने बच्चों को मानकों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही स्कूलों में किचन गार्डन विकसित कर हरी सब्जियों को भोजन में शामिल करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जिन विद्यालयों में एलपीजी गैस की सुविधा नहीं है, वहां शीघ्र व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जीर्णशीर्ण विद्यालयों को लेकर जिलाधिकारी ने मानसून से पहले मरम्मत कार्य पूरा करने के निर्देश भी दिए।